अभियोजन संचालक को 15 साल का रिकार्ड पेश करने के दिए निर्देश

जबलपुर। हाई कोर्ट ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद कहा कि प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन संचालनालय में पूर्णकालिक कर्मचारियों को पार्ट टाइम का बता कर बीए एलएलबी का कोर्स करने की अनुमति देने में घोटाला हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल आफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार 2006 के बाद केवल फुल टाइम कोर्स संचालन की ही अनुमति है। अभियोजन संचालनालय द्वारा पूर्णकालिक कर्मचारियों को विधि पाठ्यक्रम करने की अनुमति देने में एक बड़े घोटाले का खुलासा संभावित है।मामला एडीपीओ भर्ती के लिए पात्रता से संबंधित है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ब्रह्मानंद पांडे ने पक्ष रखा। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ अभियोजन संचालनालय के संचालक को खुद के हलफनामा पर पिछले 15 साल का रिकार्ड पेश करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने पूछा है कि किन परिस्थितियों में कितने ऐसे फुल टाइम कर्मचारियों को विधि कोर्स करने की अनुमति दी। यह भी बताएं कि ये अनुमति फुल टाइम कोर्स के लिए थे या पार्ट टाइम के लिए। इन पाठ्यक्रमों में दी गई डिग्रियों की क्या वैधानिकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि स्वयं का शपथ पत्र पर उक्त तथ्य और रिकार्ड पेश नहीं किए गए तो संचालक अभियोजन संचालनालय को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा। मामले पर अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी। यह खुलासा तब हुआ जब याचिकाकर्ता भोपाल निवासी सीमा वहाने ने बताया कि उसे भोपाल के मदन महाराज निजी महाविद्यालय ने बीए एलएलबी कोर्स करने सुबह 7 से 9

कैग की रिपोर्ट में मप्र पुलिस फेल

वारदात हुए 12 घंटे गुजर गए, तब पहुंची डायल-100

● भोपाल

मप्र में डायल-100 सेवा को लेकर कैग (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा- दुष्कर्म, घरेलू हिंसा, महिला अपहरण जैसी गंभीर घटनाओं में FRV (फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल) दल घटनास्थल पर 12 घंटे देरी से पहुंची। कैग ने 2016 से 2019 के दौरान की घटनाओं को लेकर असेसमेंट किया था। डायल-100 की परिकल्पना थी कि FRV दल डिस्पैचर से घटना की सूचना प्राप्त होने के बाद शहरी क्षेत्रों में 5 मिनट में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचेगी। कैग ने अपने असेसमेंट में पाया कि 13.2त्न मामलों में ही FRV 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुंची। कई मामलों में FRV घटनास्थल पर 31 से 720 मिनट यानी 12 घंटे की देरी से पहुंची। इसमें महिलाओं से जुड़ी गंभीर घटनाएं शामिल थीं। 49प्रश घटनाओं में यह असेसमेंट किया गया। 51त्न मामलों में डिस्पैच या FRV को घटनाओं की जानकारी नहीं मिली। 2.5 लाख

घटनाओं में स्त्रऋ्क देरी से पहुंची। इसमें से 14.8त्न सिर्फ स्त्रऋ्क के पहुंचने में देरी देखी गई। ग्वालियर और इंदौर में स्त्रऋ्क पर जरूरत के हिसाब से कम स्टाफ तैनात किया गया। सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन में भी अनियमितता पाई गई है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इंटरवेशन और उद्यम संसाधन योजना समाधान सहित डायल 100 के प्रोजेक्ट के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्ताव के लिए मुंबई की मेसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड को बतौर कंसल्टेंट 6 महीने के लिए नियुक्त किया गया। इसके लिए 1 करोड़ का भुगतान भी किया गया। इसने स्त्रऋ्क का मसौदा जून 2014 में प्रस्तुत किया, लेकिन विभाग ने छक्क आने से पहले सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए सितंबर 2014 में निविदा जारी की गई। इसमें ब्ङ्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया था और मई 2015 में सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए ठेका दिया गया। छक्क बनाने के लिए तैनात की गई कंसल्टेंट कंपनी 2009-19 के दौरान विभाग द्वारा चयनित कंपनी के लेखापरीक्षक थे, लेकिन केपीएमजी ने इस हित के टकराव की जानकारी नहीं दी। शासन ने भी बात स्वीकार की और कहा कि चयन के समय केपीएमजी विभाग का सलाहकार नहीं था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि डीजीपी ने बोलियों के प्राप्त होने के बाद क्वॉलिफाइंग क्राइटेरिया को कम करने को संदिग्ध बताते हुए दूसरी कंपनी को अनुचित लाभ दिया।

क्लर्क निकला करोड़पति, बंगला-गाड़ी देख भौंचक्के रहे गए अधिकारी

मुख्यमंत्री चौहान ने मोगरे का पौधा लगाया

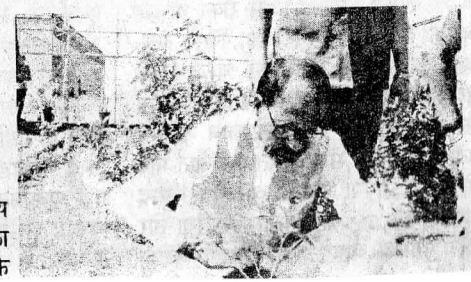

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजकीय विमान तल (स्टेट हैंगर) परिसर में दूधिया मोगरे का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान अपने संकल्प के

मध्यप्रदेश में
निर्माण कार्य
हजार करो

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री
सड़क निर्माण कार्यों के
हजार करोड़ रूपए की मं
का आभार माना है। मुख
कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र
केन्द्रीय सड़क परिवहन
गडकरी के मार्गदर्शन में
बिछाया जा रहा है। मध्य
मिल रहा है। मध्यप्रदेश
एवं अन्य मार्गों की सौं
चौहान ने सभी प्रदेशवा
श्री मोदी और केन्द्रीय मं
आभार माना है। मुख्यम
मध्यप्रदेश के इंदौर और
के इंदौर-एदलाबाद खं
लेन बनाने के लिए 11
और उज्जैन-बदनावर ख
1352 करोड़ 56 लाख
है। दोनों मार्गों की कुल
होगी। उन्होंने कहा कि म
एवं अन्य मार्गों के रूप
गुणवत्तापूर्ण मार्गों के
यातायात की सुगमता के
आर्थिक गतिविधियों में

यौन शोषण की
ने नहीं कराई F

Central Chronicle

Saturday, 12 March 2022, Bhopal | Year 66 | No. 157 | City Edition | Pages 8| Rs. 4/-

Dial 100 late by 19 minutes in cities and 31 minutes in villages

CAG report revealed, report laid on assembly table, many questions raised

Anil Sharma, Gwalior

In the report of the Comptroller and Auditor General of the country, many questions have been raised on the functioning of Dial-100 started in MP. In these, the matter of not giving immediate response even after spending more is serious. By law, dial-100 has to reach within 5 minutes in urban areas and 30 minutes in rural areas for emergency calls. But it has been seen that it is reaching the city in 24 minutes and in rural areas in 56 minutes.

The report of the CAG was prepared on the basis of the financial year ended 31 March 2020 and has been laid on the table of the Legislative Assembly. Jitendra Tiwari, Deputy Accountant General, Principal Accountant General's Office, Madhya Pradesh, Gwalior said that this report has been prepared regarding Dial-100.

It was revealed in this report that Dial-100 could not achieve its objectives due to not reaching the city and rural areas on average time. Dial-100 arrived late by 19 minutes to 31 minutes especially in cases of rape, kidnapping and domestic violence. Not only this, the year 2016-19 did not see any improvement in emergency calls and this delay defeated the objectives of Dial-100 launched from 1st November 2015 to provide quick response.

Since the state government started this project at a cost of 632.94 crores to upgrade the centralized emergency system from the police. The police department made arrangements in this model that a fleet of call center 1-response vehicles and technical support would be outsourced to the system integrator. The report clarified that the police department considered 20 out of every 100 calls to be actionable and only 2 of these found data in support of 1-response vehicle.

The CAG report has clarified to the government in the project of Dial-100 that the reason for the failure to achieve the objectives is the lack in the structure and implementation of the contract management system, so it should be reviewed once again and carried forward so that the objective for which Dial-100 has to be identified so that he can find it.

Data was not functional in many vehicles

The CAG report revealed that the Dial-100 vehicle did not show any interest in technical equipment, due to which mobile data terminals were not found in many vehicles and the ones that were installed were not functional.

मध्यप्रदेश

दैनिक भास्कर, ग्वालियर, शनिवार, 12 मार्च, 2022

• 8 सड़कों के लिए कंसल्टेंट को फीस में दिए 17 करोड़

वास रोड 339 करोड़ में बनी
ाले ने कमा लिए 1124 करोड़

सरकार के जवाब में एक सड़क के निर्माण की अलग-अलग लागत

भोपाल-देवास सड़क निर्माण में डीपीआर के हिसाब से लागत 463.40 करोड़ आई। जबकि सरकारी प्रतिवेदन में इसे 640 करोड़ रुपए और टेंडर में 420 करोड़ 64 लाख रुपए बताया गया है। इस मार्ग पर 31 जनवरी 2022 तक 1124 करोड़ रुपए यानी मूल लागत के साढ़े तीन गुना वसूल किए जा चुके हैं। इस सड़क पर 1 फरवरी 2021 से 31 जनवरी 2022 के बीच 172.14 करोड़ रुपए टोल वसूला गया। टोल शर्तों के हिसाब से इस सड़क पर 19 अक्टूबर 2033 तक यानी 11 साल और टोल वसूला जाना है यानी यह राशि 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। इस तरह सड़क निर्माण में खर्चा 420.63 करोड़ और कमाई 2324 करोड़ रुपए होगी।

कहां-किस सड़क के लिए कितनी कंसल्टेंसी फीस दी

सड़क	कंसल्टेंट कंपनी	भुगतान (रु.)
भोपाल-देवास	सांई कंसल्टिंग,भोपाल	4,91,95,996
इंदौर-उज्जैन	स्मेक इंडिया,गुड़गांव	3,53,09,021
खंडवा-बुरहानपुर	साई कंसल्टिंग	49,06,990
लेबड़-जावरा	ईस्ट कंसल्टेंट्स	2,45,40,682
दमोह जबलपुर	लायन इंजीनियर	56,54,100
लेब-मानपुर	केएंडजे नागपुर	46,89,404
देवास बायपास	एलएन मालवीय	14,59,200
बैतूल-सारणी	आजाद जैन एसो.	4,41,19,440

कैग का खुलासा : मप्र में अपराध की सूचना पर 100 में से सिर्फ 2 कॉल पर ही पहुंची डायल-100 की एफआरवी

शहरों में 24 तो गांवों में 56 मिनट में पहुंच रही एफआरवी, जबकि 5 से 30 मिनट में पहुंचनी चाहिए

भोपाल | सदन में रखी गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि संकटकालीन परिस्थितियों के लिए मध्यप्रदेश में शुरू की गई पुलिस की डायल-100 सेवा उद्देश्य से असफल हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जघन्य अपराधों की सूचना मिलने पर मदद के लिए डायल-100 की फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल (एफआरवी) भेजने के लिए 632.34 करोड़ की योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। इसके सिस्टम की पड़ताल में पता चला है कि डायल-100 की गाड़ियां हर 100 कॉल में से मात्र 2 में ही मौके पर भेजी गई हैं। इन गाड़ियों को इमरजेंसी कॉल मिलने के बाद शहरी क्षेत्रों में 5 मिनटऔर ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचना होता है, लेकिन इस मामले में एफआरवी फेल रही। डायन-100 शहरी क्षेत्र में 24 मिनट में और ग्रामीण क्षेत्र में 56 मिनट में पहुंची। वर्ष 2016 से 2019 के बीच इमरजेंसी कॉल के रिस्पांस टाइम में कोई सुधार नहीं हुआ, लिहाजा इस सर्विस का उद्देश्य ही विफल रहा। इस सिस्टम में सुधार के लिए सालाना 104 करोड़ रुपए खर्च किए, इसके बावजूद कैग ने पाया कि डेटा की गुणवत्ता और प्रभावी निगरानी ठीक नहीं थी। कैग ने सरकार से डायल-100 की खामियों की तुरंत व्यापक समीक्षा के लिए कहा है।

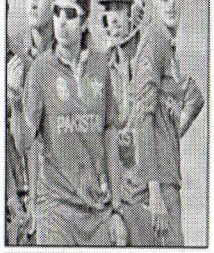

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस

मध्यप्रदेश राजस्थान हरियाणा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से प्रकाशित

वर्ष 16 ● अंक 13 ई-पेपर के लिए लॉगइन करें -www.hindustanexpress.online भोपाल, शनिवार 12 मार्च 2022 email - hindustanexpressbhopal@gmail.com, hindustanexpresshe@gmail.com मूल्य 2.00 रुपया, पृष्ठ 8

डायल 100 आपातकालीन प्रणाली पर लेखापरीक्षक ने उठाये सवाल

इस प्रणाली की सफलता के लिए अभी समीक्षा की आवश्यकता

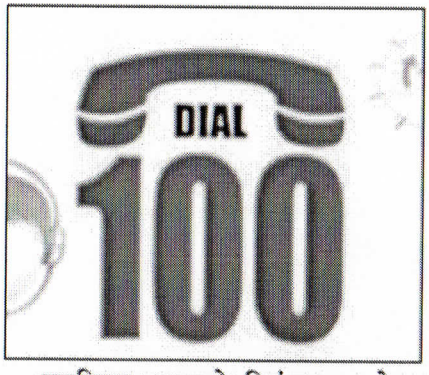

यह प्रतिवेदन गुरुवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में सौंपा

ग्वालियर। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने मध्यप्रदेश में डायल 100 आपातकालीन प्रक्रिया पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया। जिसे मध्यप्रदेश विधानसभा के पटल पर संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत गुरुवार को प्रस्तुत किया गया। इसमें निष्कर्ष निकाला गया कि परियोजना में ठेका प्रबंधन, प्रणाली संरचना और कार्यान्वयन में काफी कमी थी। जिसके चलते उद्देश्यों की प्राप्ति ठीक ढंग से नहीं हो सकी। इसलिये डायल 100 की प्रणालीगत सफलता हेतु समीक्षा की

उल्लेखनीय है कि प्रधान महालेखाकार ने उक्त विषय पर नवम्बर 2015 से मार्च 2022 की अवधि तक कुल 8 जिलो में परियोजना के क्रियान्वयन की लेखा परीक्षा की गई। इसमें जो सामने आया वह काफी चौंकाने वाले परिणाम थे जैसे कि डायल 100 के द्वारा संकटकालीन कॉल प्राप्त होने पर शहरी क्षेत्र में 5 मिनिट और ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनिट के भीतर घटना स्थल पर पहुंचना जरूरी था। जबकि औसतन प्रक्रिया काफी विलंब भरी रही। ग्रामीण क्षेत्र में औसतन घटना स्थल पर 56 मिनिट बाद डायल 100 वाहन पहुंचा। वहीं शहर क्षेत्र में 5 मिनिट की जगह 25 मिनिट घटना स्थल पर पहुंचने में लगे। इसके साथ ही इस प्रणाली में किये गये प्रत्येक 100 कॉल में से मात्र 20 कॉल को कार्यवाही हेतु वर्गीकृत किया। वहीं इनमें से भी केवल दो कॉल को फर्स्ट रिस्पांस हेतु माना। इसके साथ ही पुलिस कर्मी भी निगरानी में सुस्त थे और जैसा प्रणाली में जरूरत थी उस हिसाब से प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया। वहीं प्रणाली के संचालन की निगरानी के लिये जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उपचारात्मक कार्यवाही के लिये विलंब कर विश्लेषण नहीं किया गया। जबकि परियोजना प्रबंध सलाहकार जिसे प्रतिवर्ष 72 लाख रुपये की लागत से अनुबंध किया गया था और तो और विभाग ने इस प्रणाली को चलाने के लिये वार्षिक रूप से औसतन

न्यूज गैलरी

कान्हा की जगह पचमढ़ी में होगा मंत्रिमंडल का चिंतन शिविर

भोपाल। 26 और 27 मार्च को प्रस्तावित शिवराज मंत्रिमंडल का चिंतन शिविर अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की जगह पचमढ़ी में होगा। इसमें सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन को और बेहतर बनाने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए मंत्रियों की समिति बनाई गई है, जो 25 मार्च तक अपना प्रतिवेदन मुख्यमंत्री सचिवालय को सौंपेगी। इसके आधार पर चिंतन शिविर में विचार करके जो निर्णय लिए जाएंगे; उन्हें एक अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। -ब्यूरो

ट्रक ने खड़े कंटेनर और पिकअप को मारी टक्कर, तीन की मौत

रीवा। रीवा-प्रयागराज नेशनल हाइवे 30 के सोहागी पहाड़ क्षेत्र में शुक्रवार तड़के हुए सड़क हादसे में तीन मैकेनिकों की मौत हो गई। यहां ट्रक ने खड़े कंटेनर और पिकअप को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को प्रयागराज रेफर किया है। मृतकों में दो मैकेनिक सतना जिले के निवासी थे और एक मैकेनिक फूलपुर प्रयागराज जिले का रहने वाला था। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर फरार चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। -नप्र

आज सीएम को जड़ी-बूटी की माला पहनाएंगी महिलाएं

श्योपुर। 19 हजार 166 प्रधानमंत्री आवास की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को श्योपुर के कराहल आएंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। आदिवासी महिलाएं सीएम का स्वागत फूलों की जगह जड़ीबूटी से तैयार माला पहनाकर करेंगी। -नप्र

शिवराज सिंह

व्यापम फर्जीवाड़े के आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जियां मंजूर

जबलपुर। हाई कोर्ट ने व्यापम फर्जीवाड़े के आरोपित चिरायु मेडिकल कालेज भोपाल के अध्यक्ष अजय गोयनका, पीपुल्स मेडिकल कालेज, भोपाल के अध्यक्ष एसएन विजयवर्गीय, इंडेक्स मेडिकल कालेज इंदौर के सुरेश सिंह भदौरिया, पीपुल्स मेडिकल कालेज में एडमीशन कमेटी के सदस्य डा. विजय कुमार पंड्या, डा. वीरेंद्र चौहान, अरुण कुमार अरोरा व डा. रवि सक्सेना की अग्रिम जमानत अर्जियां मंजूर कर ली है। -नप्र

एम्स की सीनियर रेसिडेंट ने की आत्महत्या की कोशिश

भोपाल। एम्स में पदस्थ एक महिला डाक्टर ने इंजेक्शन का ओवर डोज लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की। डाक्टर (सीनियर रेसिडेंट) की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है। एम्स प्रबंधन ने घटना की सूचना गुरुवार रात को बागसेवनिया पुलिस को दी थी, जबकि घटना चार दिन पहले की बताई जाती है। -नप्र

उमा भारती फिर शराबबंदी की मांग पर अड़ीं, कह

नईदुनिया खबर पर नजर

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के ठीक एक दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने फिर शराबबंदी की मांग तेज कर दी है। शुक्रवार को मीडिया के साथ बातचीत में उमा भारती ने कहा कि मैंने गुनगा (भोपाल) से शराबबंदी अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। अब मैं गांव या शहर में शराब दुकानों के सामने खड़ी होने लगूंगी। ऐसा करने से जनमत स्पष्ट होगा और जागरूकता भी आएगी। नशाबंदी के लिए समाज और शराबबंदी के लिए सरकार को अगुवाई करना पड़ेगी, क्योंकि शराब दुकानें तो सरकार की नीति से खुलती हैं। गौरतलब है कि गुनगा में एक शराब दुकान के सामने उमा भारती खड़ी हो गई थीं, तो पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो गया।

उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस मेरा समर्थन करना चाहती है, तो करे। इसका इंतजार न करें कि मैं झंडा लेकर चलूंगी और वह सब मेरे पीछे चलेंगे। इसे सामाजिक अभियान बनाना है, राजनीतिक नहीं। जिसे लगता है कि शराब नहीं बिकनी चाहिए, वह जहां जितना विरोध कर सकता है करे। ये पूछने पर कि क्या अभियान में मुख्यमंत्री शामिल होंगे? उन्होंने कहा ये बात उनसे पूछिए। मुख्यमंत्री ने मुझे जन जागरूकता से अभियान शुरू करने को कहा है। मैंने कहा है कि निषिद्ध स्थानों पर शराब की दुकानें हैं, वहां से शुरू करिए, उन्हें हटाइए।

क्या राजनीतिक दलों के

सवाल-जवाब

- कहा- अब मैं गांव या शहर में शराब दुकानों के सामने खड़ी होने लगूंगी
- एक दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान से हुई थी उमा की बातचीत

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। ● फाइल फोटो

कैग ने कहा- पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण

गड़बड़ी ● डायल-100 के 632 करोड़ के टेंडर में पुलिस महानिदेशक ने की गड़बड़ी

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। डायल 100 योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए सलाहकार कंपनी के चयन में पुलिस महानिदेशक स्तर पर गड़बड़ी की गई। निर्धारित शर्तें में बदलाव कर दूसरे बोलीदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। डायल 100 परियोजना के 632 करोड़ के टेंडर की प्रक्रिया दोषपूर्ण रही। विधानसभा में शुक्रवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) के प्रतिवेदन में कहा गया कि वर्ष 2015 में आमंत्रित इस टेंडर में वरीयता क्रम में पहला बोलीदार (मेसर्स पीडब्ल्यूसी प्राइवेट लिमिटेड) चयनित हुआ था, लेकिन तकनीकी मूल्यांकन को आधार बनाकर इसे चयन से बाहर कर दिया गया। इसके आधार पर मेसर्स ग्रांट थार्नटन प्राइवेट लिमिटेड पात्र हो गया। कैग ने कहा कि यह सारी प्रक्रिया दोषपूर्ण थी और दूसरे बोलीदार को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। कैग ने राज्य सरकार के उस तर्क को भी नामंजूर कर दिया, जिसमें कहा गया था कि तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने अपनी सूझबूझ से 1.19 करोड़ की बचत की। कैग ने कहा कि डीजीपी को मामले में पुनर्विचार के लिए इसे क्रय समिति को वापस करना था या नया टेंडर कराना था।

दुष्कर्म, अपहरण जैसे मामलों में भी देर से पहुंची पुलिस: एक नवंबर 2015 से लागू डायल 100 योजना में शहरों में पांच और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल को घटना स्थल पर पहुंचना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दुष्कर्म, अपहरण, घरेलू हिंसा जैसे अपराधों में भी डायल 100 वाहन विलंब से पहुंचे। शहरी क्षेत्रों में औसत समय 24 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 56 मिनट रहा। इसने डायल 100 प्रणाली के उद्देश्य को विफल कर दिया।

कॉल फारवर्ड करने में भी देरी: इसमें प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम एक फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल उपलब्ध कराया गया था। इसमें पुलिसकर्मियों सहित तीन कर्मचारी रहने थे लेकिन भौतिक सत्यापन में पाया गया कि किसी में भी अपेक्षित संख्या टर्मिनल का उपयोग विधिवत नहीं किया गया। कॉल प्राप्त होने के तीन मिनट के भीतर उसे आगे प्रेषित करने की व्यवस्था है, लेकिन 22 प्रतिशत मामलों में ही यह

महिलाओं से संबंधित घटनाओं में डायल-100 के पहुंचने में विलंब

घटना का प्रकार	घटनाएं	विलंब से आगमन
वर्ष 2016		
घरेलू हिंसा	821	289
पारिवारिक विवाद	4,288	1,345
महिला अपहरण	155	60
दुष्कर्म	37	19
सामूहिक दुष्कर्म	73	28
वर्ष 2017		
घरेलू हिंसा	16,315	5,783
पारिवारिक विवाद	26,530	9,043
महिला अपहरण	636	283
दुष्कर्म	313	163
सामूहिक दुष्कर्म	459	192
वर्ष 2018		
घरेलू हिंसा	18,569	7,868
पारिवारिक विवाद	94,841	34,919
महिला अपहरण	1,464	652
दुष्कर्म	705	375
सामूहिक दुष्कर्म	1,481	647
वर्ष 2019		
घरेलू हिंसा	28,574	11,899
पारिवारिक विवाद	1,46,826	56,040
महिला अपहरण	1,894	833
दुष्कर्म	1,149	587
सामूहिक दुष्कर्म	2,229	1,021

15 हजार करोड़ के नहीं दिए उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रदेश सरकार को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में जो राशि मिली, उसमें से 15 हजार करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए गए। इसकी वजह से सभी सहायता अनुदानों को बिना शर्त वाले अनुदान के रूप में लेखों में दर्ज किया गया। कैग की रिपोर्ट में इस पर सवाल उठाए गए। 2020-21 के वित्त लेखे रिपोर्ट में बताया गया कि 2018-19 से 2020-21 में 19 हजार 604 उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागों ने नहीं दिए। इनमें सर्वाधिक 14 हजार 135 करोड़ रुपये के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2018-19 के हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजने वालों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामाजिक कल्याण एवं निशक्तजन कल्याण विभाग शामिल हैं।

ब्लैंक या अनुचित कॉल की समीक्षा ही नहीं की

कैग ने विश्लेषण में पाया कि वर्ष 2016 से 2020 की अवधि में डायल 100 में सालाना 102.9 लाख कॉल प्राप्त हुए थे, जिनमें 20.7 लाख काल ही कार्रवाई के योग्य पाए गए। 82.2 लाख कॉल ब्लैंक, अनुचित या ऐसे थे, जिनका पता नहीं मिल सका। विभाग को इसकी समीक्षा करके यह पता करना था कि गैर कार्रवाई योग्य काल के रूप में जिन्हें वर्गीकृत किया गया, वे वास्तव में गैर कार्रवाई योग्य ही थे या नहीं पर ऐसा नहीं किया गया। मिस्ड कॉल डेस्क भी स्थापित नहीं की गई। 2015 से 2020 के दौरान किसी भी मिस्ड या ब्लैंक कॉल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। समीक्षा तंत्र स्थापित करने की सिफारिश।

fb.me/NavaBharat.Social
twitter.com/Nava_Bharat
youtube.com/NavaBharatYT

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1938 से

खेल

ग्वालियर | शनिवार | 12 मार्च 2022 | वर्ष 27 | अंक 36 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00 | www.navabharat.com

डायल 100 शहर में 19 मिनट और देहात में पहुंच रही 31 मिनट की देरी से

कैग रिपोर्ट में खुलासा विधानसभा पटल पर रखा प्रतिवेदन, उठाए कई सवाल

(अनिल शर्मा)

ग्वालियर 11 मार्च. देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में म.प्र. में शुरु की गई डायल-100 की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाये हैं. इनमें अधिक खर्चे के बाद भी तत्काल रिस्पांस न देने का मामला गंभीर है.

कायदे से डायल-100 को शहरी क्षेत्रों में 5 मिनट में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर संकटकालीन कॉल आने पर पहुंचना है. लेकिन देखने में आया है कि शहर में 24 मिनट में और ग्रामीण क्षेत्रों में 56 मिनट में पहुंच रही है.

कैग की रिपोर्ट 31 मार्च 2020 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के आधार पर तैयार की गई और इसे विधानसभा के पटल पर रखा गया है. प्रधान महालेखाकार कार्यालय मध्यप्रदेश ग्वालियर के उपमहालेखाकार प्रशासन जीतेन्द्र तिवारी ने बताया कि यह रिपोर्ट डायल-100 को लेकर तैयार की गई है. इस रिपोर्ट में सामने आया कि डायल-100 औसत समय पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में न पहुंचने से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाई.

खासकर बलात्कार, अपहरण और घरेलू हिंसा के मामलों में भी डायल-100 19 मिनट से 31 मिनट तक की देरी से पहुंची. इतना ही नहीं वर्ष 2016-19 में संकटकालीन कॉल को लेकर कोई सुधार नहीं देखा गया और इस विलंब ने त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए 1 नवम्बर 2015 से शुरु की गई डायल-100 के उद्देश्यों को विफल कर दिया. चूंकि पुलिस से केन्द्रीयकृत आपातकालीन प्रणाली को उन्नत कराने के लिए राज्य शासन ने 632.94 करोड़ की लागत से यह परियोजना शुरु की.

पुलिस विभाग ने इस मॉडल में व्यवस्था बनाई की कॉल सेंटर 1-रिस्पांस व्हीकल का बेड़ा और तकनीकी सहायता सिस्टम इंटीग्रेटर से आउटसोर्स की जाएगी. इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि पुलिस विभाग ने प्रत्येक 100 कॉल में से 20 को कार्रवाई योग्य माना और इनमें से मात्र 2 में 1-रिस्पांस व्हीकल के समर्थन में डेटा मिला.

सीएजी की रिपोर्ट ने डायल-100 की परियोजना में शासन को स्पष्ट किया है कि उद्देश्यों की प्राप्ति में विफलता का कारण ठेका प्रबंधन प्रणाली संरचना और कार्यान्वयन में कमी है इसलिए इसको लेकर एक बार फिर नये सिरे से समीक्षा कर आगे बढ़ाया जाए जिससे जिस उद्देश्य के लिए डायल-100 की पहचान है वह उसे मिल सके.

कई व्हीकल में क्रियाशील नहीं थे डेटा

सीएजी की रिपोर्ट ने उजागर किया कि डायल-100 के व्हीकल में तकनीकी उपकरणों को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई गई जिसके कारण कई वाहनों में मोबाइल डेटा टर्मिनल नहीं मिले और जिनमें लगे भी थे वह क्रियाशील नहीं थे.

उत्तर प्रदेश चुनाव में बी

कैग रिपोर्ट: निविदा प्रकिया, निजी कंपनियों के चयन पर भी सवाल

2.50 लाख मामलों में मौके पर देर से पहुंची डायल 100

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. शहरी क्षेत्र में तीन मिनट तो ग्रामीण में अधिकतम 30 मिनट में पुलिस सहायता मुहैया कराने के दावे के साथ वर्ष 2015 में मप्र में शुरू की गई डायल-100 उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकी है। हाल यह हैं कि चार साल में 2.50 लाख मामलों में डायल 100 मौके पर देर से पहुंची। इसका खुलासा शुक्रवार को विधानसभा के पटल पर रखी गई भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) की 2020 की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2019 तक कॉल रिसीव होने के तीन मिनट में मदद मुहैया कराने के मामले 22 फीसदी ही हैं। 75 फीसदी मामलों में चार से 60 मिनट का तो कुछ मामलों में 12 घंटे तक लगे। डायल-100 पर आने वाले एक करोड़ से अधिक कॉल्स में से महज 20.7 लाख ही कार्रवाई योग्य पाए गए। अनपुयोगी कॉल्स की संख्या 80.2 लाख है, जो 80 फीसदी से अधिक है। विभाग ने मिस्ड कॉल डेस्क नहीं बनाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि समय पर मदद नहीं मिलने का दुष्परिणाम गंभीर अपराध मसलन बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, अपहरण आदि के रूप में सामने आए।

अधिकारियों ने रिस्पॉन्स टाइम को लेकर प्रभावी कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में डायल-100 योजना में तय मानदंडों की समीक्षा और दूसरे चरण में सेवा देने वाली निजी कंपनियो के प्रदर्शन को बेहतर करने की अनुशंसा की है। बता दें, एक नवंबर 2015 को 632.94 करोड़ की लागत से डायल-100 परियोजना शुरू की गई थी। कैग ने डायल-100 आपातकालीन प्रणाली की भोपाल, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, नरसिंहपुर और विदिशा जिले की रिपोर्ट तैयार की।

- विभाग ने निजी एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य के प्रभावी मूल्यांकन के लिए कॉल के विश्लेषण और सत्यापन सुनिश्चत नहीं किया।
- जो डाटा दिया गया उसमें 79 फीसदी घटनाओं में या तो रिक्त थे या अमान्य अंक भरे गए थे। जो डेटा की सत्यता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
- विभाग ने कुल जिले में अतिरिक्त मानव संसाधन होने के बावजूद एफआरबी में पर्याप्त लोग मुहैया नहीं कराए।